ऋण प्रदान किए गए हैं। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध मे राजस्थान राज्य की क्या स्थिति है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ बैंको द्वारा किसी नीति का अनुपालन किया जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) और (ख) बैंक कमजोर वर्गों को तथा ऐसे लोगों के लिये जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं को निरन्तर आधार पर, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमो के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान देश मे बैंको ने (सहकारी समितियो सहित) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 33.51 लाख उधारकर्ताओं को 1,220.53 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा राजस्थान के मामले मे उसी अवधि के दौरान 1.6 लाख उधारकर्ताओ को 44.37 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्यिक बैंकों ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अतर्गत कमजोर वर्गों के ऋणकर्ताओ को सहायता प्रदान की है। दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश मे कमजोर वर्गों से सबधित 235.53 लाख उधारकर्ताओ को 8365.09 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इसमें से राजस्थान में 9.8 लाख उधारकर्ताओं को 380.06 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया।

Evasion of customs duty by importers

111. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether of late there has been an increase in the number of cases of evasion of customs duty by the importers;

(b) if so, what is the number of such cases detected during the current year; and

(c) what steps have been taken to check such evasion of customs duty?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (DIGVIJAY SINGH): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

देश में कपड़े का उत्पादन

112. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है तथा इस समय वास्तव में कितने मीटर कपड़े का उत्पादन होता है ;

(ख) कपड़े की मांग को ध्यान में रखते हुए 1990-91 के अन्त तक कपड़े का उत्पादन कितना होगा ; और

(ग) उक्त उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

वस्त्र तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकम देवनारायण यादव) : (क) वर्ष 1987 के लिए कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-91 के लिए कपड़े की आवश्यकता का अनुमान 13,570 मिलियन मीटर लगाया गया है। वर्ष 1990-91 के लिए कपड़े का अनुमानित उत्पादन 17,568 मिलियन मीटर है। देश मे कपड़े के उत्पादन के कुछ भाग का प्रयोग निर्यातों के लिए और औद्योगिक फैब्रिकों के लिए भी किया जाता है।

(ख) खपत पैटर्न के आधार पर आठवीं योजना के लिए वस्त्र उद्योग पर कार्यदल ने वर्ष 1990-91 के अन्त तक कपड़े का उत्पादन 18,559 मिलियन मीटर होने का अनुमान लगाया है।

(ग) उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के के लिए खर्च होने वाली सही राशि इस तथ्य

को ध्यान में रखते हुए ठीक-ठीक नहीं बताई जा सकती कि कपड़े का अधिकांश उत्पादन विकेन्द्रीकृत हथकरघा तथा विद्युत-करघा क्षेत्रों में किया जाता है।

व्यापार सन्तुलन में घाटा

113. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1989-90 के दिसम्बर माह के दौरान व्यापार संतुलन मे कितना घाटा था तथा 1990-91 के इसी माह में कितना घाटा होने का अनुमान है, तथा इस घाटे को कम करने के लिए आयात मे कमी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है और 1991 के अंत मे तक इस घाटे को कितना कम किया जा सकता है,

वाणिज्य मंत्री साथ में वित्त और व्यय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री सुब्रमण्यम स्वामी) : अनन्तिम आकड़ो के अनुसार माह दिसम्बर, 1989, के दौरान भारत का व्यापार घाटा 833 56 करोड रुपये रहा। अक्टूबर, 1990 तक के उपलब्ध अनन्तिम आकडे उस माह के दौरान 1091.05 करोड रुपये का व्यापार घाटा दर्शाते है। इस स्तर पर दिसम्बर. 1990 के दौरान, और 1991 के बाद के संभावित व्यापार घाटे का ठीक-ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है। सरकार ने व्यापार घाटे को स्थिर रखने के उद्देश्य से अनावश्यक मदों के आयात को कम करने के लिए कई उपाय किए है। इनमें पूंजीगत सामान, कच्चे माल, संघटको और उपभोज्य वस्तुओं की कुछ मदों को, खुले सामान ल इसेंस से लाइसेंसिंग श्रेणियो में रखना आदि शामिल हैं। साथ ही साथ निर्यात बढाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे है।

बजट घाटा और विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

114. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 के वर्ष के बजट घाटे में कोई कमी आई है; यदि नहीं तो इस समय बजट घाटा कितना है;

(ख) सरकार बजट घाटे को कम करने के लिए 1990-91 के अन्त तक क्या कदम उठाने का विचार रखती है तथा वर्ष के अन्त तक इसको कितना कम किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने मे कुछ कठिनाइया आ रही हैं और क्या सरकार ने इन कठिनाइयों को हल करने के लिए कोई पहल की है, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1990-91 के बजट मे अनुमानित स्तर की तुलना मे केन्द्रीय सरकार के बजट घाटे में परिवर्तनो की सशोधित अनुमानों मे प्रतिविम्बित किया जाएगा, जिन्हे 1991-92 के बजट दस्तावेजों मे दर्शाया जाएगा।

(ख) सरकार ने चालू वर्ष में बजटीय घाटे को नियंत्रित रखने के लिए पहले ही अनेक उपाय किए है। इनमे से, व्यय मे मितव्ययिता बरतने के लिए किए गए उपायों, नए संसाधन जुटाने के प्रयासो सहित राजस्व संग्रहो को तेज करने, निर्यात बढ़ाने और विदेशी सहायता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने का उल्लेख किया जा सकता है। इन उपायो का प्रभाव कुछ समय के बाद पता लगेगा।

(ग) जी नही।

Insurance Claims of November 1984 Riot Victims

115. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many victims of November, 1984 riots had in-